



2026:AHC:17910

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2601/2026**

सोनू यादव

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- धीरज कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में अंकित है, जिसे स्वयं पीड़िता द्वारा इस आरोप के साथ दर्ज कराया गया है कि वह एक विधवा एवं गरीब महिला है तथा प्रार्थी ने उसे ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और उक्त घटना का वीडियो भी बनाया। अब वह उसे उसकी कामुक इच्छा पूरी न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में एफ.आई.आर. के कथन को दोहराया है, किंतु कथित रूप से कई बार किए गए बलात्कार की घटना की तिथि एवं समय का कोई उल्लेख नहीं है। एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। अतः यह तर्क दिया गया कि यह झूठा फँसाने का मामला है और प्रार्थी को दुर्भावना एवं कुटिल मंशा से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



असत्य एवं निराधार आरोपों के आधार पर फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि आवेदक विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 31.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी सोनू यादव को मुकदमा अपराध संख्या 592/2025, धारा 64(2)(एम), 115(2), 352, 351(3), 333 बी.एन.एस., थाना मेजा, जनपद प्रयागराज में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।



v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम